भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1895

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की बैठकें

†1895. श्री मनीश तिवारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए), चंडीगढ़ द्वारा अपनी स्थापना के बाद से आयोजित बैठकों की तिथिवार संख्या और प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 'राइट्स' के नेतृत्व में गठित नवीनतम व्यवहार्यता समिति के निष्कर्षों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो परियोजना की व्यवहार्यता के संबंध में उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ की सरकारों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार को कोई संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके प्रस्तुत की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसकी समय-सीमा क्या है;

(ङ) मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) क्या भागीदारी वाली राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच कोई अंतर-सरकारी वित्तीय साझाकरण सूत्र प्रस्तावित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन 28.04.2023 को किया गया था। यूएमटीए की पहली, दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमशः 18.07.2023, 13.12.2023 और 02.09.2024 को हुई थीं।

(ख) से (च): संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, योजना आरंभ करने और विकास के लिए संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत आयोजना और कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मार्गदर्शी दस्तावेजों के रूप में कार्य करती हैं। केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरी रेल आधारित प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है।

वर्तमान में, चंडीगढ़ में मेट्रो परियोजना के संबंध में कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

*****